



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2002 ई0

अवधायण 01, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 1473 A/कार्मिक-2/2002

देहरादून, 22 नवम्बर, 2002

अधिसूचना/प्रकीर्ण

पृष्ठ आ0-208

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तरांचल के श्री राज्यपाल, राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के प्रकरण को पिनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002

- 1- संक्षिप्त नाम— यह नियमावली उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 कहलायेगी।
- 2- परिभाषाएं— जब तक प्रसंग से अन्य कोई अर्थ अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,

(क) “सरकार” से तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

(ख) “सरकारी कर्मचारी” से तात्पर्य ऐसे लोक सेवक से है, जो उत्तरांचल राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण—किसी बात के होते हुए भी कि ऐसे सरकारी कर्मचारी का वेतन उत्तरांचल की संचित निधि से अन्य साधनों से आहरित किया जाता है, ऐसे सरकारी कर्मचारी भी, जिसकी सेवायें, उत्तरांचल सरकार ने किसी कम्पनी, निगम, संगठन, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार किसी अन्य राज्य सरकार को अर्पित कर दी हों, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये, सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा।

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में, "परिवार का सदस्य" के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे—

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उसके साथ रहता/रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के संबंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त संबंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या संबंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक् की गई हो/पृथक् किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नहीं होगा, या/सम्मिलित नहीं होगी जो आगे के लिये, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा (custody) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

3—सामान्य—

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राज्य कर्मचारी रहते हुए आत्यंतिक रूप से सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता से अपने कार्यों का निर्वहन करना होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राज्य कर्मचारी रहते हुए उसके व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त विशिष्ट (Specific) या विवक्षित (implied) शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करना होगा।

(3) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध—

1— कोई सरकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्यस्थल पर, उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

2—प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए "यौन उत्पीड़न" में, प्रत्यक्षतः या अन्यथा कामवासना से प्रेरित कोई ऐसा अशोभनीय व्यवहार सम्मिलित है जैसे कि—

(क) शारीरिक स्पर्श और कामोदीप्त प्रणय संबंधी चेष्टायें,

(ख) यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना,

(ग) कामवासना-प्रेरित फ़ितियाँ,

(घ) किसी कामोत्तेजक कार्य/व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन, या

(ङ) यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण।"

(4) कोई सरकारी कर्मचारी घरेलू कार्य में सहायता के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोज़गार नहीं करेगा।

4—सभी लोगों के साथ समान व्यवहार—

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सभी जाति, पंथ (sect) या धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करना होगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी किसी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।

4-क—मादक पान, तथा औषधि का सेवन— कोई सरकारी कर्मचारी,

(क) किसी क्षेत्र में, जहाँ यह तत्समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा मादक औषधि संबंधी प्रवृत्त किसी विधि या दृढ़ता से पालन करेगा,

(ख) अपने कर्तव्यपालन के दौरान किसी मादक पान या औषधि के प्रभावधीन नहीं होगा और इस बात का सम्यक् ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन किसी भी ऐसे पेय या भोजन के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है;

(ग) सार्वजनिक स्थान में किसी मादकपान अथवा औषधि के सेवन में अपने को विरत रखेगा;

(घ) मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान में उपस्थित नहीं होगा;

(ङ) किसी मादकपान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—एक— इस नियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान या परिसर (जिसमें कोई सँवारी वाहन भी सम्मिलित है) से है, जहाँ भुगतान अथवा अन्य प्रकार से जनता को आने-जाने की अनुज्ञा हो।

स्पष्टीकरण—दो— कोई क्लब जहाँ;

(क) सरकारी कर्मचारियों से गिन व्यक्तियों को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति देता है; अथवा

(ख) जिसके सदस्यों को उरामें अतिथि के रूप में गैर-सदस्यों को आमंत्रित करने की अनुज्ञा हो, भले ही सदस्यता सरकारी कर्मचारियों के लिए ही सीमित हो।

स्पष्टीकरण एक के प्रयोजनार्थ ऐसा स्थान समझा जायेगा जहाँ पर जनता आ-जा सकती हो या उसे आने-जाने की अनुज्ञा हो।

5—राजनीति तथा चुनावों में हिस्सा लेना—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का या किसी ऐसी संस्था का, जो राजनीति में हिस्सा लेती है, सदस्य न होगा और न अन्यथा उससे संबंध रखेगा और न वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा लेगा, उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करेगा, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

उदाहरण

राज्य में 'क', 'ख', 'ग' राजनीतिक दल हैं।

'क' वह दल है जो सत्ता में है और जिसने तत्समय सरकार बनाई है।

'अ' एक सरकारी कर्मचारी है।

यह उप-नियम 'अ' पर सभी दलों के संबंध में, जिसमें 'क' दल भी, जो कि सत्ता में है, सहित प्रतिषेध करेगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया (activity) में, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्ति पैदा करती है, हिस्सा लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से उसकी मदद करने से रोकने का प्रयत्न करे, और, उस दशा में जबकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या क्रिया में भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति से मदद करने से रोकने में असफल रहे, तो वह इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देगा।

उदाहरण

'क' एक सरकारी कर्मचारी है।

'ख' एक "परिवार का सदस्य" है, जैसी कि उसकी परिभाषा नियम 2 (ग) में दी गयी है।

'आ' वह आन्दोलन या क्रिया है, जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति ध्वंसक है या उसके प्रति ध्वंसक कार्यवाहियों करने की प्रवृत्ति पैदा करती है।

'क' को विदित हो जाता है कि इस उप-नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, 'आ' के साथ 'ख' का सम्पर्क आपत्तिजनक है। 'क' को चाहिए कि वह 'ख' के ऐसे आपत्तिजनक सम्पर्क को रोकें। यदि 'क', 'ख' के ऐसे सम्पर्क को रोकने में असफल रहे, तो उसे इस मामले की एक रिपोर्ट सरकार के पास भेज देनी चाहिए।

(3) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न है कि कोई आन्दोलन या क्रिया इस नियम की परिधि में आती है अथवा नहीं, तो इस प्रश्न पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(4) कोई सरकारी कर्मचारी, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी (local Authority) के चुनाव में, न तो मतार्थन (canvassing) करेगा न अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, और न उसके संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा;

परन्तु;

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, जो ऐसे चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने के अपने अधिकार को प्रयोग में ला सकता है, किन्तु उस दशा में जब कि वह वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, वह इस बात का कोई संकेत न देगा कि उसने किस ढंग से अपना वोट डालने का विचार किया है अथवा किस ढंग से उसने अपना वोट डाला है।

(2) केवल इस कारण से कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अन्तर्गत उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के यथोचित पालन में, कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव के संचालन में मदद करता है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

स्पष्टीकरण— किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, अपनी सवारी गाड़ी या निवास—स्थान पर, किसी चुनाव चिन्ह (electoral symbol) के प्रदर्शन के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने इस उप-नियम के अर्थ के अन्तर्गत, किसी चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग किया है।

उदाहरण

किसी चुनाव के संबंध में, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी या मतदान क्लर्क, की हैसियत से कार्य करना उप-नियम (4) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होगा।

5-क— प्रदर्शन तथा हड़तालें—

कोई सरकारी कर्मचारी—

(1) कोई प्रदर्शन नहीं करेगा या किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा, जो भारत की प्रगुता तथा अखंडता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक सुव्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के प्रतिकूल हो अथवा जिससे न्यायालय का अवमान या मानहानि होती हो अथवा अपराध करने के लिए उत्तेजना मिलती हो, अथवा

(2) स्वयं या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के संबंध में न तो कोई हड़ताल करेगा और न किसी प्रकार की हड़ताल करने के लिए प्रेरित करेगा।

5-ख— सरकारी कर्मचारियों का संघों (Association) का सदस्य बनना— कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे संघ का न तो सदस्य बनेगा और न उसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य अथवा कार्य—कलाप भारत की प्रगुता तथा अखंडता के हितों या सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हों।

6— समाचार पत्रों (Press) या रेडियों से सम्बन्ध रखना—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन (periodical publication) का, पूर्णतः या अंशतः, स्वामी नहीं बनेगा, न उसका संचालन करेगा न उसको सम्पादन-का या प्रबन्ध में भाग लेगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उरा दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो अथवा जब वह अपने कर्तव्यों का सदभाव से निर्वहन कर रहा हो, किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा और छद्मनाम से अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में किसी समाचार-पत्र या पत्रिका को कोई पत्र नहीं लिखेगा।

परन्तु उरा दशा में जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृत पत्र (Broadcast) के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7—सरकार की आलोचना— कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या छद्मनाम से, या स्वयं अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख में या समाचार-पत्रों को भेजे गये किसी पत्र में, या किसी सार्वजनिक कथन (public utterance) में, कोई ऐसी तथ्य की बात (statement of fact) या न्त व्यक्त नहीं करेगा—

(1) जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना हो या उत्तरांचल सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी चालू या हाल की नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो; अथवा

(2) जिससे उत्तरांचल सरकार और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उत्पन्न पैदा हो सकती हो; अथवा

(3) जिससे केन्द्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के आपसी सम्बन्धों में उत्पन्न पैदा हो सकती हो;

परन्तु इस नियम में व्यक्त कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्त किए गए किसी ऐसे कथन या विचारों के सम्बन्ध में लागू न होगी, जिन्हें उसने अपने सरकारी पद की हैसियत से या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के यथोचित पालन में व्यक्त किया हो।

उदाहरण

(1) 'क' को, जो एक सरकारी कर्मचारी है, सरकार द्वारा नौकरी से बर्खास्त किया गया है। 'ख' को, जो कि एक दूरारा सरकारी कर्मचारी है, इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से (publicly) यह कहे कि दिया गया स्पष्ट अवैध, अत्यधिक या अन्यायपूर्ण है।

- (2) कोई लोक अधिकारी स्टेशन 'क' से स्टेशन 'ख' को स्थानान्तरित किया गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, उक्त लोक अधिकारी को स्टेशन 'क' पर ही बनाए रखने से संबंधित किसी आन्दोलन में भाग नहीं ले सकता।
- (3) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसे मामलों में सरकार की नीति की आलोचना करे, जैसे किसी वर्ष के लिए निर्धारित गन्ने का भाव, परिवहन का राष्ट्रीयकरण, इत्यादि।
- (4) कोई सरकारी कर्मचारी निर्दिष्ट आयात की गई वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए कर की दर के संबंध में कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।
- (5) एक पड़ोसी राज्य उत्तरांचल की सीमा पर स्थित किसी भू-खण्ड के संबंध में दावा करता है कि वह भूखण्ड उसका है। कोई सरकारी कर्मचारी उक्त दावे के संबंध में, सार्वजनिक रूप से, कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।
- (6) किसी सरकारी कर्मचारी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह किसी विदेशी राज्य के इस निश्चय पर कोई मत प्रकाशित करे कि उसने उन रियायतों को समझा कर दिया है जिन्हें वह एक दूसरे राज्य के राष्ट्रियों (nationals) को देता था।

8—किसी समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के सामने साक्ष्य—

- (1) उप नियम (3) के उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जाँच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।
- (2) उस दशा में, जबकि उप-नियम (1) के अन्तर्गत कोई स्वीकृति प्रदान की गई हो, कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार से साक्ष्य देते समय, उत्तरांचल सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति की आलोचना नहीं करेगा।
- (3) इस नियम में दी हुई कोई बात, निम्नलिखित के संबंध में लागू न होगी:—
 (क) साक्ष्य, जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, उत्तरांचल की विधान-सभा या संसद द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने दी गई हो, अथवा
 (ख) साक्ष्य, जो किसी न्यायिक (Judicial) जाँच में दी गयी हो।

9—सूचना का अनधिकृत संचार— कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय सरकार के किसी सागान्य अध्यादेशानुसार या उसको सौंपे गए कर्तव्यों का सदभाव के साथ (in good faith) पालन करते हुए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई सरकारी लेख्य या सूचना किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिस ऐसी लेख्य या सूचना देने या संचार करने का उसे अधिकार न हो, न देगा और न संचार करेगा।

स्पष्टीकरण—किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को दिए गये अभ्यावेदन में किसी पत्रावली की टिप्पणियों का या टिप्पणियों में से उद्धरण देना इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत सूचना का अनधिकृत संचार माना जायेगा।

- 10—चन्दा— कोई सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी ऐसे धर्मार्थ प्रयोजन के लिए चन्दा या कोई अन्य वित्तीय सहायता माँग सकता है या स्वीकार कर सकता है या उसके इकट्ठा करने में भाग नहीं ले सकता है, जिसको सम्बन्ध डाक्टरों सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों से हो, किन्तु उसे इस बात की अनुमति नहीं है कि वह इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए चन्दा, आदि माँगे।

उदाहरण

कोई भी सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना जनता के उपयोग के लिए किसी नल-कूप (ट्यूब वेल) के खेदन के लिए या किसी सार्वजनिक घाट के निर्माण या मरम्मत के लिए, चन्दा जमा नहीं कर सकता।

- 11—भेंट—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो—

(क) स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट-सम्बन्धी न हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भेंट, अनुग्रह—धन पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, या

(ख) अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को, जो उस पर आश्रित हो, किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट-सम्बन्धी न हो, कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा:—

परन्तु वह किसी जातीय मित्र (personal friend) से सरकारी कर्मचारी के मूल धेतन का दशांश या उससे कम मूल्य का एक विवाहोपहार या किसी रीतिगत अवसर पर इतने ही मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसे स्वीकार करने की अनुमति दे सकता है। किन्तु सभी सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपहारों को दिए जाने को भी रोकने का भरसक प्रयत्न करें।

उदाहरण

एक कर्मचारी के नागरिक यह निश्चय करते हैं कि 'क' को, जो एक सब गण्डलीय अधिकारी है, गाढ़ के दौरान उसके द्वारा की गई सेवाओं के सराहना स्वरूप एक घड़ी भेंट में दी जाय, जिसका मूल्य उसके मूल धेतन के दशांश से अधिक है। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, 'क' उक्त उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है।

- 11—क—कोई सरकारी सेवक—

(1) न तो दहेज देगा और न लेगा उसके देने या लेने के लिए दुष्चेरित करेगा, और

(2) न, यथास्थिति, बधु या वर के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की माँग करेगा।

रपष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रति रोध अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 28, वर्ष 1961) में इसके लिये दिया गया है।

12—सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन— कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि उसने सरकार के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो कोई गान-पत्र या विदाई-पत्र नहीं लेगा, न कोई प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा और न अपने सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक आमोद में उपस्थित होगा।

परन्तु इस नियम में दी हुई कोई बात, किसी ऐसे विदाई समारोह के संबंध में लागू न होगी, जो सारतः (substantially) निजी तथा अरीतिक स्वरूप का हो, और जो किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में उसके अवकाश प्राप्त करने (retirement) या स्थानान्तरण के अवसर पर आयोजित हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में आयोजित हो जिसने हाल ही में सरकार की सेवा छोड़ी हो।

उदाहरण

'क', जो डिप्टी कलेक्टर है, रिटायर होने वाला है। 'ख' जो जिले में एक दूसरा डिप्टी कलेक्टर है, 'क' के सम्मान में एक ऐसा भोज दे सकता है जिसमें चुने हुए व्यक्ति आमंत्रित किये गये हों।

13—असारकारी व्यापार या नौकरी— कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यापार या कारोबार में भाग नहीं लेगा और न ही कोई रोजगार करेगा।

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी, इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई सामाजिक या धनार्थ प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक (occasional) कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन नहीं पड़ती है तथा वह ऐसा कार्य हाथ में लेने से एक महीने के भीतर ही, अपने विभागाध्यक्ष को और यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष हो, तो सरकार को, इस बात की सूचना दे दें, किन्तु, यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश दे तो वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने उसे हाथ में ले लिया है, तो बन्द कर देगा। विरुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक किस्म की रचनाओं से भिन्न रचनाओं के प्रकाशन की दशा में, पुस्तकें लिखने तथा प्रकाशित करने और उनके लिये स्वामित्व (रायल्टी) स्वीकार करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जायेगी—

(1) पुस्तक पर सरकार की मुद्रणानुज्ञप्ति (imprimatur) अंकित न हो।

(2) पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लेखक का नाम बिना उसके सरकारी पदनाम के दिया गया हो, किन्तु पुस्तक के बहिरावरण (dust-cover) पर जिसमें जनता को लेखक का परिचय दिया जाता है, सरकारी पदनाम देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) लेखन पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर अपने नाम से यह उल्लेख कर दे कि पुस्तक में वर्णित लेखक के विचारों और टीका टिप्पणियों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की है और पुस्तक के प्रकाशन से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) लेखक को यह बात भी सुनिश्चित करनी चाहिये कि पुस्तक में तथ्य अथवा मत संबंधी कोई ऐसा कथन नहीं है जिसमें राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की किसी वर्तमान अथवा हाल की नीति या कार्य की कोई प्रतिकूल आलोचना की गई है।

(5) सरकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बिक्री से होने वाली आय पर एकमुक्त धनराशि अथवा लगातार प्राप्त होने वाली धनराशि दोनों ही रूप में स्वागित्य (रायल्टी) स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि:-

(क)-(1) पुस्तक केवल नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गई है, अथवा

(2) पुस्तक केवल सरकारी नियमों, विनियमों या कार्यविधियों का संकलन मात्र है,

तो लेखक (सरकारी कर्मचारी) से, जब तक कि राज्यपाल विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दें, इस बात की अपेक्षा की जायेगी कि वह आय का एक-तिहाई सामान्य राजस्व के खाते में उस दशा में जमा करे जब कि आय 2500 रु० से अधिक हो या यदि वह आकर्षक रूप में प्राप्त होने वाली तथा 2500 रु० वार्षिक से अधिक हो।

(ख)-(1) पुस्तक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी के दौरान प्राप्त ज्ञान की सहायता से लिखी गई है, किन्तु वह सरकारी नियमों, विनियमों और अथवा कार्यविधियों का संग्रह मात्र नहीं है बरन् सम्बन्धित विषय पर लेखक के विद्वत्पूर्ण अध्ययन को प्रकट करती है, अथवा

(2) रचना के लेखक के सरकारी पद से न तो कोई सम्बन्ध है और न होने की सम्भावना है,

तो पुस्तक की बिक्री की आय या स्वागित्य (रायल्टी) से उसके द्वारा आकर्षक या अनावर्षक रूप में प्राप्त आय का कोई भाग सामान्य राजस्व के खाते में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2—यह भी निश्चित किया गया है कि उत्तरांचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 13 के अधीन सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐसी साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक किस्म की रचनाओं के प्रकाशन के लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है जिनमें उनके सरकारी कार्य से सहायता नहीं ली गई है और प्रतिशत के आधार पर स्वागित्य (रायल्टी) स्वीकार करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। किन्तु सरकारी कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रकाशनों में उन शर्तों का कड़ाई से पालन किया गया है जिनका उल्लेख ऊपर प्रस्तर-1 में किया गया है और उनसे सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है।

3—किन्तु उन सभी दशाओं में सरकार की पूर्ण स्वीकृति ली जानी चाहिये जिनमें लगातार स्वागित्य (रायल्टी) प्राप्त करने का प्रस्ताव हो। इस प्रकार की अनुमति देते समय रचना के पाठ्य-पुस्तक के रूप में नियत किये जाने और ऐसी दशा में सरकारी पद के दुरुपयोग होने की सम्भावना पर भी विचार किया जाना चाहिए।

- 14—**कम्पनियों का निबन्धन, प्रवर्तन (promotion) तथा प्रबन्ध**—कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जब कि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनी के निबन्धन प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग न लेगा, जो इंडियन कम्पनीज ऐक्ट 1913 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, निबद्ध हुआ है।

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 (ऐक्ट नं० 2 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (ऐक्ट नं० 21 1860), या किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक वैज्ञानिक या धार्मिक समिति के निबन्धन प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

और भी परन्तु यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी सहकारी समिति के प्रतिनिधि के रूप में किसी बड़ी सहकारी समिति या निकाय (Body) में उपस्थित हो तो उस बड़ी सहकारी समिति या निकाय के किसी पद के निर्वाचन की इच्छा न करेगा। वह ऐसे निर्वाचन में कबल अपना मत देने के लिए भाग ले सकता है।

- 15—**बीमा करदार—**कोई सरकारी कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट 1912 (ऐक्ट नं० 2 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 (ऐक्ट नं० 21 1860) या किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक वैज्ञानिक या धार्मिक समिति के निबन्धन प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

- 16—**अवयवको (manor) का संरक्षकत्व (guardianship)**—कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जब कि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो उसी पर उक्ति किसी अवयवको के अतिरिक्त किसी अन्य अवयवको (manor) के शरीय या सम्य के विधेय संरक्षण (legal guardianship) के रूप में कार्य नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—1—इस नियम के प्रयोजन के लिये, आश्रित (dependant) से तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी बच्चों तथा सौतेले बच्चों और बच्चों से है, और इसके अन्तर्गत उसको जनक (parents) बहिन भाई भाई के बच्चे और बहिन के बच्चे भी सम्मिलित होंगे यदि वे उसके साथ निवास करते हों और उस पर पूर्णतः आश्रित हों।

स्पष्टीकरण—2—इस नियम के प्रयोजन के लिये, समुचित प्राधिकारी (Appropriate Authority) वही होगा जैसा कि नीचे दिया गया है—

विभागाध्यक्ष, डिप्टीजन के

कमिशनर या कलेक्टर के लिए: राज्य सरकार

जिला जज के लिए: उच्च न्यायालय का प्रशासकीय जज

अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए: संबंधित विभागाध्यक्ष

- 17—**किसी सचची (रिश्तेदार) के विषय में कार्यवाही—**

(1) जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में, जो उसका सचची हो चाहे वह समझ दूर या निकट का हो, कोई प्रस्ताव या मत प्रस्तुत करता है या कोई अन्य कार्यवाही करता है चाहे यह प्रस्ताव मत या कार्यवाही

उक्त रावजी को पक्ष में हो अथवा उसके विरुद्ध हो, तो वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव, मत या कार्यवाही के साथ यह बात भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि वह व्यक्ति विशेष उसका सबधी है अथवा नहीं है और यदि वह उसका ऐसा सबधी है तो इस सबध का स्वरूप क्या है।

(2) जब किसी प्रवृत्त विधि नियम या आज्ञा के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रस्ताव, मत या किसी अन्य कार्यवाही के सबध में अंतिम रूप से निर्णय करने की शक्ति रखता है और जब वह प्रस्ताव, मत या कार्यवाही किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के सबध में है, जो उसका सबधी है चाहे वह सबध दूर अथवा निकट का हो और चाहे उस प्रस्ताव मत या कार्यवाही का उक्त व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो या अन्यथा वह कोई निर्णय नहीं देगा, बल्कि वह उस मामले का अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रस्तुत कर देगा और साथ ही उस प्रस्ताव करने के कारण बता देना के स्वरूप को भी स्पष्ट कर देगा,

18—सदरों लगाना—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी किसी लगी हुई पूजी (investment) में सदरों नहीं लगायेगा।

स्पष्टीकरण—इसमें ही अस्थिर मूल्य वाली प्रवृत्तियों को सूचा (volatile) कर के न निकाले के सबध में यह स्पष्टा ज्ञापित है कि वह इस नियम के अन्तर्गत् लगी हुई पूजियों में सदरों लगाता है।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूजी उप नियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

19—लगाई हुई पूजियाँ—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी न तो कोई पूजी इस प्रकार रखेगा लगायेगा जोर न उसकी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा। फिर से उसने सरकार के कानून के परिपालन में उत्पन्न या प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो,

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या लगी हुई पूजी उपर्युक्त स्वरूप की है अथवा नहीं तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

उदाहरण

कोई जिला जज उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को कोई सिन्धुमूठ खोतान या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा।

20—उधार देना और उधार लेना—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उरावें प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो रूपरुपा उधार नहीं देगा और न किसी व्यक्ति को व्याज पर रूपरुपा उधार देगा;

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी किसी असरकारी नौकर को अग्रिम रूप से वेतन दे सकता है, या इस दाव के हत हुए भी कि ऐसा व्यक्ति (उसका मित्र या सखी) उचित प्रतिकार की रथा-नीय रीमाओ के भीतर कोई गूने रखता है, वह अपने किसी जातीय मित्र या सखी को, बिना व्याज के, एक छोटी रकम वाला ऋण दे सकता है।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी बैंक सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापारिक काम के अनुसार न तो किसी व्यक्ति से, अपने स्थानीय अधिकार की सीमाओं के भीतर, रुपया उधार लेगा और न अन्यथा अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वह उस व्यक्ति के वित्तीय बंधन (pecuniary obligation) के अन्तर्गत हो जाय और न वह सिवाय उस व्यक्ति के ही उस पर प्रतिष्ठित प्रतिकूलता की पूरी स्वीकृति जाया करेगी, अपने परिवार के किसी सदस्य को इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति देगा।

[illegible]

(3) यदि कोई सरपंच या अधिकारी इस प्रकार के किसी पद पर नियुक्त या सेवा करण पद में है तो उसे सम्बन्धित इस उप विभाग 1) या उप विभाग 2, के किसी अधिकारी को लिखा जा सकता है कि वह अपने पद पर नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा नियुक्त है, कि वह एक दफ्तर में कार्य कर रहे हैं व वे अपने पद पर अनुसार कार्य करेगा जिन्हें सम्बन्धित प्राधिकारी दे।

(4) एक बार मैं कह रहा था कि इस में जो रास्ता है उसी ही सामान्य प्राणी जैसी संज्ञा रखता होगा और दूसरे मामले में असाधारणत्व का प्रमाण मिलेगा।

21- विशेष और आवृत्ति प्रमाण (Habitual indebtedness)-

[illegible]

22—चल अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति—

(1) यदि राक्षसी दानवों की मदद से आपका पाला लोभ में लक्ष्मि प्रदिवशी दो दशकी पूर्ण जागृकी है या तो स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति या अन्यथा न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे देवेगा।

1999 में भी एसे गैर सरकारी जो गिरती नियमित और ख्यातिप्राप्त (ICJPLCC) व्यपारी से गोपनीय द्वारा सम्बन्धित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करने आवश्यक होगा।

(5) सामुचित प्राधिकारी

(क) राज्य सरकार से सम्बन्धित किसी सरकारी कर्मचारी के प्रसंग में उप नियम 1, तथा (4) के प्रयोजनों के निमित्त राज्य सरकार तथा उप-नियम 2) के निमित्त विभागाध्यक्ष होंगे।

(ख) अन्य सरकारी कर्मचारियों के प्रसंग में उप-नियम 1) से (6) तक के प्रयोजनों के निमित्त, विभागाध्यक्ष होंगे।

23. राज्य से कर्मचारियों के कार्यों तथा चरित्र का प्रतिसमर्थन (Vindication) —
कोई सरकारी कर्मचारी जिसमें उस देश में जब कि उसने सरकार की पूर्ण रक्षार्थी प्राप्त कर ली है किसी ऐसे सरकारी कार्य का जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारक भावना का विषय बन गया हो के प्रतिसमर्थन करने के लिये किसी समाचार-पत्र की शरण नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम की किसी बात के अन्वये यह नहीं समझा जाये कि किसी सरकारी कर्मचारी को अपने चरित्र के लिये उस देश में या अन्य देशों में अपने कार्य के कारण होने वाले प्रतिकूल भावनाओं का प्रतिकूल प्रतिकार करना है।

24. असरकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अत्याचार (1) 15/11/2002 का मसौदा —
राज्य सरकार के किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत या संस्थागत रूप से अत्याचार करने का प्रयास करेगा उसे राज्य सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जायेगी।

स्पष्टीकरण—सरकारी कर्मचारी को यह स्वीकृति नहीं दी जाती कि अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा अत्याचार किया गया हो। यह नियम के अन्वये अत्याचार का अर्थ है कि कोई व्यक्ति या संस्था जिस व्यक्ति या संस्था के सम्बन्ध में अत्याचार करने का प्रयास करेगा उसे राज्य सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जायेगी।

उदाहरण

किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो कोई भी व्यक्ति या संस्था अत्याचार करने का प्रयास करेगा उसे राज्य सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जायेगी। यह नियम के अन्वये अत्याचार का अर्थ है कि कोई व्यक्ति या संस्था जिस व्यक्ति या संस्था के सम्बन्ध में अत्याचार करने का प्रयास करेगा उसे राज्य सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जायेगी।

24. क—सरकारी सेवकों द्वारा अत्याचार—कोई सरकारी कर्मचारी उचित माध्यम से और ऐसे उद्देश्यों के प्रसारण के निमित्त राज्य सरकार समय-समय पर जारी कर व्यक्तित्व तथा या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार भ्रष्टा किन्हीं अन्य प्रतिकारों का कोई अत्याचार नहीं करेगा, नियम 24 का स्पष्टीकरण इस नियम पर भी लागू होगा।

25. अनाधिकृत वितीय व्यवस्थाएं—कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई ऐसी वितीय व्यवस्था नहीं करेगा जो कि राज्य सरकार के नियमों के अन्वये अनाधिकृत रूप से या

- 29- बिना मूल्य दिये सेवाओं का उपयोग करना—कोई सरकारी कर्मचारी बिना मूल्य दिये और पैसे बिना मूल्य दिये बिना किसी ऐसी सेवा या आमोद (Entertainment) का स्वयं प्रयोग नहीं करेगा जिससे लिये कोई किराया या मूल्य या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो।

उदाहरण

जब तक ऐसा करना कर्मचारी के एक मात्र के रूप में निर्धारित न किया गया हो, कोई सरकारी कर्मचारी

(1) बिना भी किराये पर चलने वाले वाहन में बिना मूल्य दिये यात्रा नहीं करेगा,

(2) बिना प्रवेश शुल्क दिये सिनेमा शो नहीं देखेगा।

- 30 द्वारा की सरकारी वाहन प्रयोग में लाया— कोई सरकारी कर्मचारी बिना किसी परमादेश के बिना किसी सरकारी वाहन को प्रयोग में नहीं करेगा जो उसी परमादेश के अधीन की है, जो किसी भी सरकारी कर्मचारी की हो जो उसी अधीन हो।

- 31- आधिकारिक कर्मचारी के अपने अधिकार— कोई सरकारी कर्मचारी बिना किसी परमादेश के बिना किसी सरकारी वाहन को प्रयोग में नहीं लायेगा जो उसी परमादेश के अधीन की है, जो किसी भी सरकारी कर्मचारी की हो जो उसी अधीन हो।

परन्तु यह नियम कि वह अपने अधिकारों पर लागू नहीं होगा, कि वह अपने अधिकारों के अधीन की है, जो किसी भी सरकारी कर्मचारी की हो जो उसी अधीन हो।

उदाहरण

'य', एक डिप्टी कमिश्नर है।

'ख', एक डिप्टी कमिश्नर के अधीन एक सहरीलदार है।

यह 'ख' से कहे कि वह उसके लिये कपड़ा खरीदवा दे।

- 32 निर्णय (Interpretation)—इस नियमों के निर्णय से सम्बन्धित कोई भी निर्णय (Interpretation) है जो उस सरकार में सम्बन्धित करना होगा तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

- 33 निरस्त (Repeal) तथा अनुवाद (Savings)—इस नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व की प्रथा को इस नियमों के तत्पर्यन्त के अन्तर्गत प्रवेश की संज्ञा—इस नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते थे, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

किन्तु प्रसिद्ध यह है कि इस प्रकार निरस्त किये गये नियमों के अधीन किसी भी कर्मचारी को इस नियमों के तत्पर्यन्त के अन्तर्गत प्रवेश की संज्ञा—इस नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते थे, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

साक्षात् से

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1473 A/Karmic-2/2002, dated November 22, 2002 for general information

No. 1473 A/Karmic-2/2002
Dated Dehradun, November 22, 2002

NOTIFICATION/MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor of Uttaranchal makes the following rules to regulate the conduct of government servants employed in connexion with the affairs of the State:-

THE UTTARANCHAL GOVERNMENT SERVANTS' CONDUCT RULES, 2002

- 1- Short title- These rules may be called the Uttaranchal Government Servants' Conduct Rules, 2002
- 2- Definition- In these rules unless the context otherwise requires:-

(a) Government means the Government of Uttaranchal;

(b) Government servants' means a such public servant who is appointed to public services and posts in connexion with the affairs of the State of Uttaranchal.

Explanation- A government servant whose services are placed at the disposal of a company, a corporation, an organization, a local authority or a local Government or the Government of another State by the Uttaranchal Government, shall for the purposes of these rules be deemed to be a government servant notwithstanding that his salary is drawn from sources other than that of the Government of Uttaranchal;

(c) "member of the family" in relation to government servant, includes

(i) The wife, son, step son, unmarried daughter, or an married step-daughters of such government servant whether residing with him or not, and, in relation to a government servant who is a woman, the husband residing with her and dependent on her, and

(ii) Any other person related, whether by blood or by marriage, to the government servant or to such government servant's wife or her husband, and wholly dependent on such government servant

But does not include a wife or husband legally separated from the government servant or a son, step-son, unmarried daughter or unmarried step daughter who is no longer, in any way dependent upon him or her, or of whose custody, the government servant has been deprived by law.

3. General

(1) every government servant shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty.

(2) Every government servant shall at all times conduct himself in accordance with the specific or implied orders of Government regarding behavior and conduct which may be in force.

(3) Prohibition of sexual harassment of working women –
No Government servant shall indulge himself in any sexual harassment to any women at his working place

(i) Every Government servant who is in charge of a working place will take suitable steps to stop sexual harassment of women.

Explanation- For the purpose of this rule the sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behavior (Whether directly or by implication) as-

- (a) Physical contact and advances,
- (b) Demand or request for sexual favours,
- (c) Sexually coloured remarks,
- (d) Showing pornography,
- (e) Any other un-welcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

(4) No Government servant will employ the children below the age of fourteen years as domestic help.

4 Equal treatment for all (1) every government servant shall accord equal treatment to people irrespective of their caste, sect or religion

(2) No government servant shall practice untouchability in any form

4 A Consumption of intoxicating drinks and drugs - A Government servant shall-

(a) Strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being,

(b) Not be under the influence of any intoxicating drinks or drug during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drinks or drug,

(c) Refrain from consuming any intoxicating drink or drug in a public place,

(d) Not appear in a public place in a state of intoxication,

(e) Not use any intoxication drink or drug to excess

Explanation- 1. For the purposes of this rule, 'public place' means any place or premises (including a conveyance) to which the public have, or are permitted to have access, whether on payment or otherwise

Explanation- 2. Any club: -

(a) Which admits persons other than government servants as members, or

(b) The members of which are allowed to invite non-members as guests thereto even though the membership is confined to government servants, shall, for purposes of Explanation 1, be deemed to be a place to which the public have or are permitted to have access.

5. **Taking part in politics and elections.** (1) No government servant shall be a member of, or otherwise associated with, any political party or any organization which takes part in politics, nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in an, other manner, any movement or organization which is, or tends directly or indirectly to be, subversive of the government as by law established.

Illustration

XYZ are political parties in the State.

X is the part in power and forms the Government of the day.

A is a government servant.

The provisions of the sub-rule apply to A in respect of all parties, including X, which is the part in power.

(2) It shall be the duty of every government servant to endeavour to prevent any member of his family from taking part in, subscribing in aid of, or assisting in any other manner any movement or activity which is, or tends directly or indirectly to be, subversive of the Government as by

law established and where a government servant fails to prevent a member of his family from taking part in, or subscribing in aid of, of make report to that effect to the government.

Illustration

A is a government servant

B is a member of the family of A, as defined in rule 2(c)

M is a movement or activity, which is, or tends directly or indirectly to be, subversive of Government as law established

A becomes aware that B's association with M is objectionable under the provisions of the sub-rule. A should prevent such objectionable association of B. If A fails to prevent such association of B, he should report the matter to the Government

If any question arises whether any movement or activity falls within the scope of this rule, the decision of the Government thereon shall be final.

(3) No government servant shall canvass or otherwise interfere or influence in connection with, or take part in, an election to any legislative or local authority:

Provided that--

(1) A government servant entitled to vote at such election may exercise his right to vote but where he does so, he shall give no indication of the nature of his position as voter or as candidate

(2) A government servant shall not be deemed to have contravened the provisions of this rule by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

Explanation- the display by a government servant on his personal vehicle, or residence, of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within meaning of sub rule (4)

5 A Demonstration and strikes- No government servant shall

(1) Engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence, or

Illustration

- (1) A, a government servant is dismissed from service by the Government. It is not permissible for B, another government servant, to say publicly that the punishment is wrongful, excessive or unjustified.
- (2) A public officer is transferred from station A to station B. No government servant can join the agitation for the retention of the public officer at station A.
- (3) It is not permissible for a government servant to criticise publicly the policy of Government on such matters as the price of sugarcane fixed in any year nationalization of transport, etc.
- (4) A government servant cannot express any opinion on the rate of duty imposed by the Central Government on specified imported goods.
- (5) A neighbouring State lays claim to a tract of land lying on the border of Uttaranchal. A government servant cannot publicly express any opinion on the claim.
- (6) It is not permissible for a government servant to put forward any opinion on the decision of foreign State to terminate the concessions given by it to the nationals of another State.

6 Evidence before committee or any other authority-

- (1) Save as provided in sub-rule (2), no government servant shall, except with the previous sanction of the Government, give evidence in connection with an inquiry conducted by any person, committee or authority.
- (2) Where any sanction has been accorded under sub-rule (1), no government servant giving such evidence shall criticise the policy of the Uttaranchal Government, the Central Government or any other State Government.
- (3) Nothing in the rule shall apply to-
 - (a) Evidence given at an inquiry before an authority appointed by the Government, by the Central Government, by the Legislature of Uttaranchal or by Parliament, or
 - (b) Evidence given in any judicial inquiry.

9. **Un authorised communication of information-** No government servant shall except in accordance with any general or special order of the Government or in the performance, in good faith, of the duties assigned to him communicate, directly or indirectly, any official document or information to any government servant or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information.

Explanation—Quotation by a Government servant in his representation to his official superior, of or from the notes in any file shall amount to unauthorised communication of information within the meaning of this rule.

10. **Subscription-** Government servant may, with the previous sanction of the Government, ask for, or accept or participate in the raising of a subscription or other pecuniary assistance for a charitable purpose connected with medical relief, education or other object of public utility; but it shall not be permissible for him to ask for subscription, etc. for any other purpose whatsoever.

Illustration

A government servant may, with the previous sanction of the Government raise subscription for the benefit of a well for the use of the village for the collection or repair of a public ghāt,

- 11- **Gifts-** A Government servant shall not without previous approval of the government-

- Accept directly or indirectly in his own behalf or in behalf of any other persons, or
- Permit any member of his family who is dependent on him to accept any gift, gratuity or reward from any person other than a close relation.

Provided that he may accept or permit any member of his family to accept from a personal friend a wedding present or a present on a ceremonial occasion of a value not exceeding Rs. 1000. All government servants shall, however, use their best endeavour to discourage even the tender of such presents.

Illustration

The citizens of a village decide to present to a sub divisional officer a watch exceeding Rs. 1000 in value in appreciation of the services rendered by him during the flood. A cannot accept the present without the previous approval of Government.

11- A No government servant shall-

- (i) Give or take or abet the giving or taking of dowry, or
- (ii) Demand directly or indirectly from the parents or guardians of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry

Explanation- for the purposes of this rule, the word 'dowry' has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961)

12. **Public demonstrations in honour of government servants-** No government servant shall, except with the previous sanction of the Government, receive any complimentary or valedictory address, or accept any testimonial, or attend any meeting or public entertainment held in his honour, or in the honour of any other government servant

Provided that nothing in this rule shall apply to a farewell entertainment of a substantially private or informal character and held in honour of a government servant on the occasion of his retirement or transfer or of any person who has recently quitted service of the Government

Illustration

A, a Deputy collector, is due to retire, B, another Deputy collector the District Magistrate gave a dinner in honour of A to which selected persons are invited

13. **Private trade or employment-** No government servant shall except with the previous sanction of the Government, engage directly or indirectly in any trade business or undertake any employment

Provided that a government servant may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature of occasional work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer and that he informs his Head of Department, and when he is himself the Head of the Department, the Government within one month of his undertaking such work, but he shall not undertake or shall discontinue, such work if so directed by the Government

The permission to write and publish books and accept royalty therefore, in the case of publication of works other than those of purely literary, artistic or scientific character, will henceforth be granted on the following condition:

- (1) The book does not bear the imprimatur of Government
- (2) The author's name appears in the first page of the book without his official designation. There may, however, be no objection to the official signature to be given on the dustcover where the author is introduced to the public.
- (3) The author gives a statement under his name on the first page of the book or at any other suitable place, that the author's views and comments in the book are entirely the responsibility of the author and Government are in no way connected with the publication of the book.
- (4) The author shall also ensure that the book does not contain any statement of fact or opinion which is in any way inconsistent of any current or recent policy or action of the State Government or Central Government or Government of any other State or local authority.
- (5) Government servants can be permitted to accept royalty but in lump sum or on a contract basis and the proceeds of the book written by them: provided that if-
 - (a) The book is written solely with the aid of the knowledge acquired in the course of service; or
 - (b) The book is a mere compilation of Government rules, regulations or procedures.

The author (Government servant) should be required, unless the Government by special order, otherwise directs to credit to the general revenue one third of the income if it is in excess of Rs. 2500 or if the income is a recurring one, it is in excess of Rs. 2500 per annum.

- (6) If the book is written with the aid of knowledge acquired by the Government servant in the course of his service but it is not a mere compilation of Government rules, regulations or procedures, but reveals the author's scholarly study of the subject, or

- (ii) The work neither has nor is likely to have any connection with the author's official position;

No part of the income realization of non-recruiting derived by him from the sale proceeds or royalties of the book need be credited to the general revenues.

2. It has also been decided that sanction of Government is not necessary under Rule 13 of the Uttaranchal Government Servants Conduct Rules, 2002 for publication by Government servants of works of literary, artistic or scientific character which are not issued for its official duties and the acceptance of royalty on percentage basis is not proposed. Government servant should, however, ensure that the publication strictly conform to the conditions mentioned in Part I above and to not infringe the provisions of the Government Servants Conduct Rules.

3. Prior sanction of Government should, however, be taken in all cases where continuing royalty is proposed. In granting such permission, the possibility of the work being prescribed as a text book and the possible income arising therefrom from such an event should also be considered.

14. **Registration, promotion and management of companies** - No government servant shall, except with the previous sanction of the Government, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company registered under the Indian Companies Act, 1913, or under any other law for the time being in force.

Provided that a government servant may take part in the registration, Promotion or management of a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (Act II of 1912), or under any other law for the time being in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act XXV of 1860), or under any corresponding law in force.

Provided further that, if a government servant attend any bigger co-operative society or body as a delegate of any co-operative society, he will not seek election for any post of that bigger society or body. He may take part in such election only for purposes of casting his vote.

15. **Insurance Business** - A government servant shall not permit his wife or any other relative who is either wholly dependent on him or is residing with him, to act as an insurance agent in the same district in which he is posted.

16. **Guardianship of minors-** A government servant may not, without the previous sanction of the appropriate authority, act as a legal guardian of the person or property of a minor other than his dependent.

Explanation 1- A dependent for the purpose of this rule means a government servant's wife, children and step-children and children's children and shall also include his parents, sisters, brothers, brother's children and sisters' children if residing with him and wholly dependent upon him.

Explanation 2- appropriate authority for the purpose of this rule shall be as indicated below:

For a Head of Department, Divisional Commissioner of a collector.	The State Government.
--	-----------------------

For a District Judge	The Administrative Judge of the High Court.
----------------------	--

For other government servants	The Head of the Department, concerned
-------------------------------	--

17. **Action in respect of a relation-** (1) Where a government servant submits any proposal, opinion or takes any other action, whether for or against any individual related to him, whether the relationship be of status of near, he shall with every such proposal, opinion or action, expressly state whether the individual is or is not related to him and if so related the nature of the relationship.

(2) Where a government servant has by any law, rule or order in force power of submitting any proposal, opinion or any other action, and that proposal, opinion or action is in respect of an individual related to him, whether the relationship be of status or near, and whether that proposal, opinion or action affects the individual favorably or otherwise, he shall take a decision, but shall send the case to his superior officer after explaining the reasons and the nature of relationship.

18. **Speculation** (1) No government servant shall speculate in any investment.

Explanation—the purchase or sale of securities of a not-a-money fluctuating value shall be deemed to be speculation in investments within the meaning of this rule.

- (2) If any Question arise whether a security or investment is of the nature related to it, sub-rule (1) the decision of the Government thereon shall be final.

19. **Investments-** (1) No government servant shall make, or permit his wife or any member of his family to make any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties

- (2) If any question arises whether a security or investment is of the nature referred to above, the decision of the Government thereon shall be final.

Illustration

A District Judge shall not permit his wife, or son, to open a cinema house or to purchase a share therein, in the district where he is posted

20. **Lending and borrowing-** (1) No government servant shall, except with the previous sanction of the appropriate authority, lend money to any person possessing land or valuable property within the local limits of his authority, or at interest to any person:

Provided that a government servant may make an advance of pay to a private servant, or give a loan of a small amount free of interest to the personal friend or relative, even if such person possess land within local limits of his authority.

- (2) No government servant shall, save in the ordinary course of business with a bank, co-operative society or a firm of standing known to him, or otherwise place himself under any obligation to any person within the local limits of his authority, for services rendered by any member of his family except with the previous sanction of the appropriate authority to enter into any such transaction:

Provided that a government servant may accept a purely temporary loan of small amount free of interest, from a personal friend or relative, or operate a credit account with a bona fide tradesman.

- (3) When a government servant is appointed or transferred to a post of such a nature as to involve him in the breach of any of the provisions of sub-rule (1) or sub-rule (2), he shall forthwith report the circumstance to the appropriate authority, and shall thereafter act in accordance with such orders as may be passed by the appropriate authority.

- (4) The appropriate authority in the case of government servants who are gazetted officers shall be the Government and in other cases the Head of the Office.

21. **Insolvency and habitual indebtedness** A Government servant shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness of insolvency. A government servant who becomes the subject of legal proceedings for insolvency shall forthwith report the full facts to the head of the office or department in which he is employed.
22. **Movable, immovable and valuable property** (.) No government servant shall, except with the previous knowledge of the appropriate authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family:

Provided that any such transaction conducted otherwise than through a regular any reputed dealer shall require the previous sanction of the appropriate authority.

Illustration

A Government servant proposes to purchase a house. He must inform the appropriate authority of the proposal. If the transaction is to be made through a regular or reputed dealer, A must also obtain the previous sanction of the appropriate authority. The same procedure will be applicable if A proposes to sell his house.

- (2) A Government servant shall not enter into any transaction involving any property exceeding in value the amount of his pay for one month, whether by way of purchase, sale or otherwise, without reporting such transaction to the appropriate authority:

Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or at the previous sanction of the appropriate authority.

Illustration

- I — A Government servant whose monthly pay is Rs 600 purchases a tap recorder for Rs. 700, or
- II — B, a Government servant whose monthly pay is Rs 2000 sells a car for Rs. 500. In either case A or B must report the matter to the appropriate authority. If the transaction is made otherwise than through a reputed dealer must also obtain the previous sanction of the appropriate authority.

- (3) At the time of first appointment and thereafter at intervals of five years, every government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property, owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, and of shares, and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with, or in any way dependent upon him. Such declarations should state the full particulars of the property, shares and other investments.
 - (4) The appropriate authority may, at any time, by general or special order, require a government servant to submit within a period specified in the order a full and complete statement of such movable immovable property held or acquired by him or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall, if so required by the appropriate authority, include details of the means by which or the source from which such property was acquired.
 - (5) The appropriate authority—
 - (a) in the case of a government servant belonging to the State service, shall for purposes of sub-rules (1) and (4), be the Government and for sub-rule (2), the Head of the Department,
 - (b) In the case of other government servants, for the purposes of sub-rules (1) to (4) shall be the Head of the Department.
23. Vindication of acts and character of government servants- No government servant shall except with the previous sanction of the Government, have recourse (E) to the press for the vindication of any official act which has been the subject-matter of adverse criticism or an attack of defamatory character.
- Explanation—nothing in this rule shall be deemed to prohibit a government servant from vindicating his private character or any act done by him in private capacity.
24. Canvassing of non-official or other outside influence No—government servant shall bring or attempt to bring whether himself personally or through a member of his family, any political or other outside influence to bear upon any question relating to him interest in respect of matters pertaining to his service.

Explanation—Any act done by the wife or husband, as the case may be, or any member of the family of a government servant and falling within the purview of this rule, shall be presumed to have been done at the instance, or with the connivance of the government servant concerned, unless the contrary shall have been proved.

Illustration

A is a government servant and B a member of the family of A: C is a political party and D is an organization under G, B, gained sufficient prominence in G and become an office bearer of D. Through D, B started sponsoring the cause of A to the extent that B sponsored some resolutions against A's official superiors. This action which will be in violation of the provisions of the above rule on the part of B shall be presumed to have been done by B at the instance, or with connivance of A unless A is able to prove that this was not so.

- 24 A. "A. Representations by Government servants—No Government servant shall whether personally or through a member of his family, make any representation to Government or any other authority except through the proper channel and in accordance with such directions as the Government may issue from time to time. The Explanation to rule 24 shall apply to this rule also."
25. Unauthorized pecuniary arrangements—No government servant shall enter into any pecuniary arrangement with another government servant or any other person so as to afford any kind or advantage to either or both of them in any unauthorized manner or against the specific, or implied, provisions of any rule for the time being in force.

Illustration

- (1) A is a senior clerk in an office and is due for officiating promotion. A is diffident of discharging his duties satisfactorily in the officiating post. B, a junior clerk, privately offers for a pecuniary consideration to help A. A and B accordingly enter into pecuniary arrangements. Both would thereby infringe the rule.
- (2) If, A the Superintendent of an office proceeds on leave, B, the senior most assistant in the office, will be given a chance to officiate. If A proceeds on leave after entering into arrangement with B for a share in the officiating allowance A and B both would commit a breach of the rule.

26. **Bigamous marriages—**(1) No government servant who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the Government, notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to him.
(2) No female government servant shall marry any person who has a wife living without first obtaining the permission of the Government.
27. **Proper use of amenities-** No government servant shall misuse or carelessly use, amenities provided for him by the Government to facilitate the discharge of his public duties.

Illustration

Among the amenities provided to government servant are cars, telephones, residences, furniture, orderlies, article of stationer, etc. Instances of misuse or careless use of these are—

- (i) Employment of government cars at government expense by members of the family of the government servant or his guests, or for other non-government work,
 - (ii) Making telephone trunk calls at Government expence on matters not connected with official work.
 - (iii) Neglect of Government residences and furniture and failure to maintain them properly, and
 - (iv) Use of government stationary for non-official work.
28. **Payment for purchases—** Unless payment by installments is customary, or specially provided, or a credit account is maintained with a bona fide tradesman, no government servant shall withhold prompt and full payment for the article purchased by him whether the purchases are made on tour or otherwise.
 29. **Use of services without payment—** No government servant shall without making proper and adequate payment, avail himself of any service or entertainment for which a hire or price or admission fee is charged.

Illustration

Unless specifically prescribed as part of duty, a government servant shall not—

- (i) Travel free of charge in any plying for hire.
 - (ii) See a cinema show without paying the admission fee.
30. Use conveyances belonging to other—No government servant shall, except in exceptional circumstances, use a conveyance belonging to a private person or government servant who is subordinate to him.
31. Purchases through subordinates—No government servant shall himself ask or permit his wife, or any other member of his family living with him to ask any government servant who is subordinate to him, to make purchases, locally or from outstation on behalf of him, his wife or other member of his family, whether on advance payment or otherwise:

Provided that this rule shall not apply to the purchases which the inferior staff attached to the government servant may be required to make.

Illustration

A is a deputy collector.

B is a talisildar under the deputy collector.

A should not allow his wife to ask B to have cloth purchased for her.

32. Interpretation—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.
33. Repeal and saving—Any rules corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules and applicable to government servant under the control of the Government of Uttaranchal are hereby repealed:

Provided that an order made or action taken under the rules repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,

Secretary.